कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 60 अंक: 07 मई 2014 मूल्य : ₹ 10

ग्रामीण भारत में कृषि आधारित उद्योग

Scanned by CamScanner

कृषि सहभागिता का पर्याय डेयरी उद्योग

डॉ. मुनिता बाफना

डेयरी क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखने के लिए सरकार समय-समय पर प्रयास करती रही है। बारहवीं योजना में पशुपालन के लिए 982 करोड़ रुपये और डेयरी विकास के लिए 3072 करोड़ रुपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है। सम्पूर्ण विश्व में भारत में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है और दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। लघु एवं सीमांत कृषकों के हित संवर्द्धन हेतु सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

किसान और कृषि श्रमिक दोनों के लिए वर्तमान में अपने परिवार तथा स्वास्थ्य को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीण मुश्किल से पूरे वर्ष रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। नरेगा या महानरेगा का लाभ भी लगभग सभी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। कृषि पूरे वर्ष रोजगार के रूप में उपलब्ध नहीं होती। यहां तक कि सघन कृषि वाले क्षेत्रों में भी, जहां काम की उपलब्धता अधिक है, कृषि खास मौसम के कुछ महीनों में ही उपलब्ध हो पाती है। ऐसी स्थिति में कृषि सहभागिता के रूप में पशुपालन को ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक माना गया है।

पशुपालन का सीधा जुड़ाव डेयरी उद्योग से है। भारत में डेयरी विकास के प्रारम्भिक प्रयास ब्रिटिश शासनकाल में उस समय से खोजे जा सकते हैं, जब रक्षा विभाग ने औपचारिक सेना के लिए दूध और घी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सैन्य डेयरी फार्म की स्थापना की थी। इस तरह पहला डेयरी फार्म 1913 में उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद शहर में स्थापित किया गया था। द्वितीय विश्वयुद्ध में भी कुछ हद तक निजी डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया गया। भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में दूध उत्पादन हेतु डेयरी उद्योग को प्राथमिकता दी।

देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 से श्वेतक्रान्ति प्रारम्भ की गई जिसे ऑपरेशन फ्लड प्रथम का नाम दिया गया। देश के 10 राज्यों में इसे प्रारम्भ किया गया जिसमें राजस्थान भी एक था। किसानों को आयअर्जक गतिविधियों में संलग्न विकास हेतु ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। आज दूध का राष्ट्रीय ग्रिड है जो 800 शहरों और कस्बों के उपभोक्ताओं को ताजे दूध की आपूर्ति करता है। आपरेशन फ्लड भारतीय डेयरी उद्योग को स्थिर एवं जर्जर स्थिति से निकालने का सुनियोजित प्रयास था। इस कार्यक्रम ने भारत में डेयरी विकास की गति को न केवल तीव्र किया अपितु भारत को विश्व के प्रथम दूध उत्पादक राष्ट्र के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है।

डेयरी क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखने के लिए सरकार समय-समय पर प्रयास करती रही है। बारहवीं योजना में पशुपालन के लिए 982 करोड़ रुपये और डेयरी विकास के लिए 3072 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

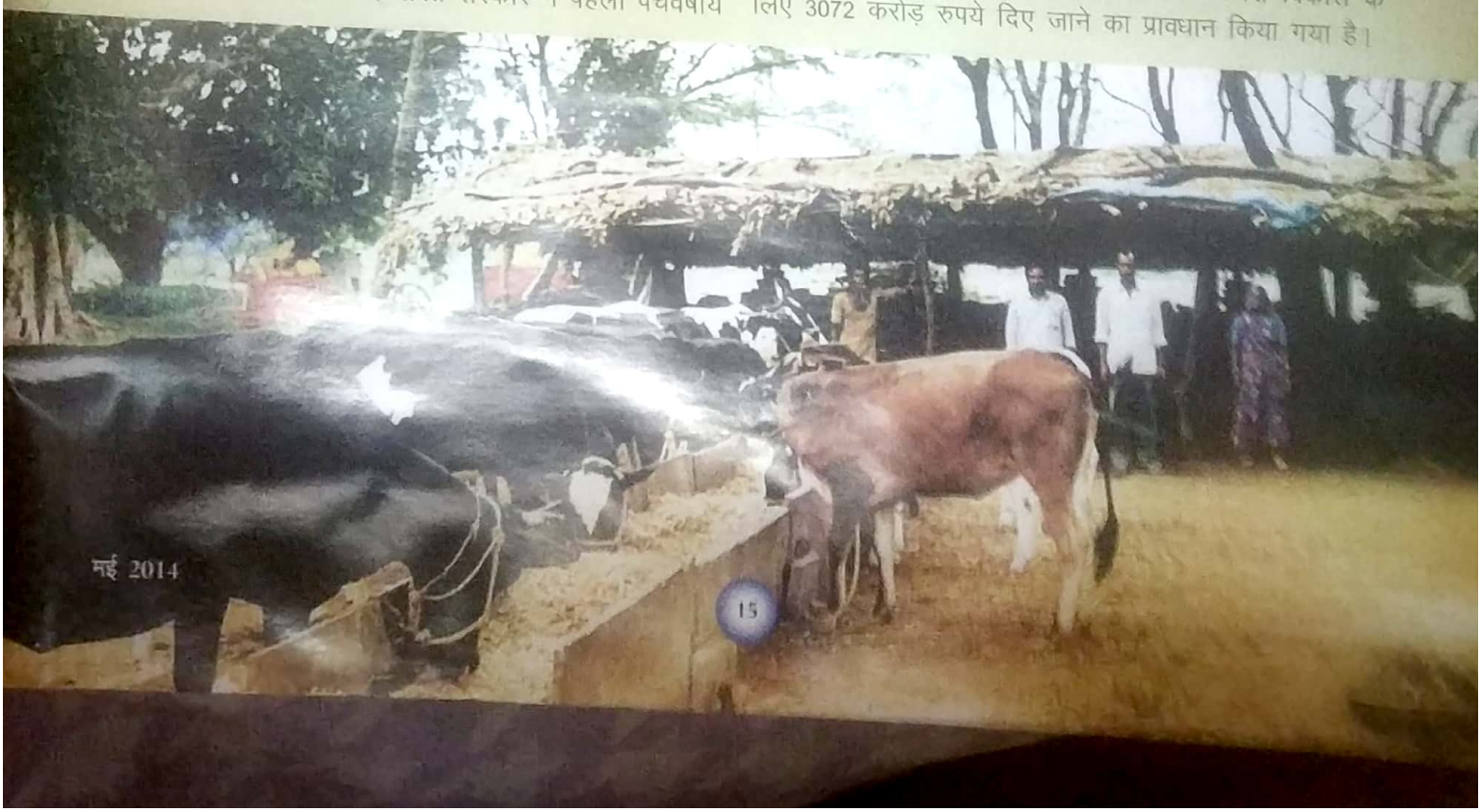

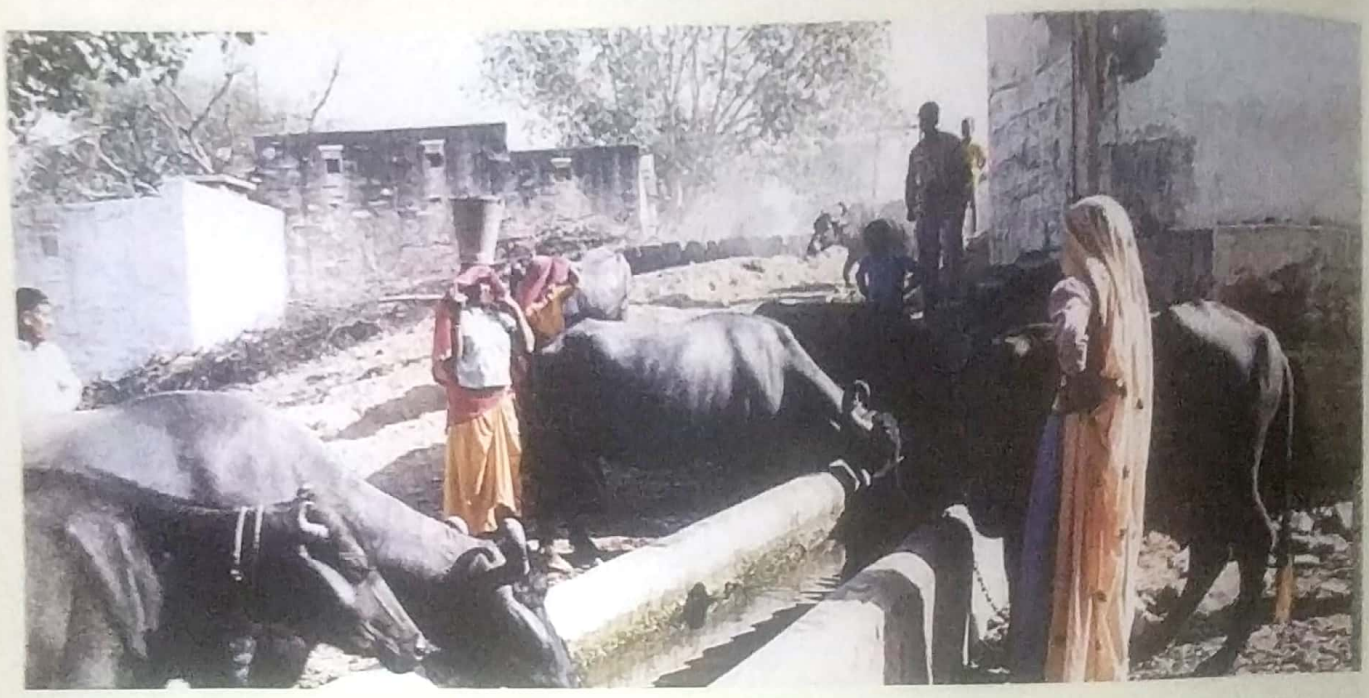

सम्पूर्ण विश्व में भारत में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है और दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। लघु एवं सीमांत कृषकों के हित संवर्द्धन हेतु सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भूतपूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा लिखित "भारत दृष्टि 2020" में राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा का उल्लेख मिलता है। उपरोक्त पांचों प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता गाय में विद्यमान है।

गाय भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ है। हमारे देश में 150 करोड़ बैलगाड़ियों से अरबों टन माल की ढुलाई की जाती है। भारत में पशु आधारित कृषि पद्धति से लगभग 30000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है जिसके परिणामस्वरूप 238 करोड़ टन डीजल की बचत होती है। इसी प्रकार गाय के गोबर को सही तरीके से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाए तो प्रति वर्ष लगभग 15 करोड़ वृक्षों की कटाई को रोक सकते हैं एवं कृषक आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

दूध एक जीवनदायी पेय है। स्तनधारी जीवों की सभी प्रजातियां मनुष्य से लेकर व्हेल तक दूध उत्पादन करती हैं। संभवतः ईसा पूर्व 6000–8000 में मनुष्य ने दुधारू पशुओं को पालना शुरू किया ताकि नियमित रूप से दूध मिल सके। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट प्रमुख दुधारू पशु हैं। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप कृषि के साथ–साथ इन दुधारू पशुओं का पालन–पोषण किया जाता है। दुग्ध उत्पादन का कार्य अधिकांशतः लघु व सीमांत किसान तथा भूमिहीन श्रमिक करते हैं। इससे समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। देश के 88 प्रतिशत गाय–बैल, 90 प्रतिशत भैंस, 72 प्रतिशत पोल्ट्री व 87 प्रतिशत सूअरों का मालिकाना हक लघु व सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों के पास है। डेयरी उद्योग का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि इससे समाज के अकुशल लोगों, विशेषकर महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है। जीवन– स्तर में वृद्धि, बढ़ते शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, बदलती अभिरुचि के कारण दूध की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अब तो दूध का विविध रूपों में प्रयोग बढ़ रहा है जैसे मक्खन, घी, छाछ, आईसक्रीम, मिल्क केक, मिल्क चॉकलेट आदि। यह प्रवृत्ति दुग्ध उत्पादकों के लिए शुभ संकेत है।

आजादी के पूर्व तक दुग्ध उत्पादन मुख्यतः असंगठित क्षेत्र के हाथों में था। दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। न केवल शहरों में अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की स्थिति खराब थी। उपभोक्ताओं के समक्ष घटिया क्वालिटी के दूध और दुग्ध उत्पाद खरीदने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। किसानों के लिए दूध व्यवसाय घाटे का सौदा हो गया था क्योंकि बिचौलियों द्वारा उनको शोषण किया जाता था।

ऑपरेशन फ्लड 1970 के दौरान किसानों ने शोषण से बचने के लिए 1945 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने हड़ताल कर दी। इस हड़ताल को वल्लभभाई पटेल व मोरारजी देसाई का समर्थन प्राप्त था। इन दोनों ने किसानों को बताया कि जब डेयरी व्यवसाय की पूरी शृंखला पर किसानों का नियंत्रण होगा तभी उन तक लाभ पहुंच पाएगा। किसानों का केवल दूध उत्पादन पर ही नहीं बल्कि दूध एकत्र करने व बेचने पर भी पूरा

Scanned by CamScanner

नियंत्रण होना चाहिए। इस हड़ताल की समाप्ति पर औपनिवेशिक सरकार ने किसानों को अपना सहकारी संघ बनाने की अनुमति दी। अंग्रेजों को पूरा विश्वास था कि गरीब अनपढ़ किसान सहकारी संघ नहीं बना पाएंगे लेकिन उनका अनुमान गलत निकला। और आज यह सफलतम संगठन के रूप में 320 लाख लीटर दूध उत्पन्न कर रहा है।

डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और पशुओं की उत्पादकता आहार और चारे की पौष्टिकता पर निर्भर करती है। कृषि भूमि पर खाद्यान्न, दलहन, तिलहन उगाने पर अधिक बल देने के कारण चारा फसल उगाने पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पशुपालन और डेयरी के लिए अध्ययन समूह के अनुसार देश में उपलब्ध पशुचारा केवल 52.4 प्रतिशत पशुओं की आवश्यकता पूर्ति कर सकता है। राजस्थान में 48 प्रतिशत और गुजरात में 37 प्रतिशत चारागाह हैं। अतः यहां दुग्ध उत्पादन अच्छा होने के कारण डेयरी उद्योग अच्छी स्थिति में है।

भारत में दुग्ध उत्पादन

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन में)
1991–92	56.03
1992–93	58.06
1993–94	65.00
1994–95	65.00
1195–96	.....
1996–97	68.02
1997–98	71.74
2000–01	98.07
2005–06	107.00
2006–07	112.08
2020 लक्ष्य	235.00

श्वेत क्रान्ति के द्वारा गुजरात में आनन्द डेयरी, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध उत्पादकता बढ़ी, लेकिन श्वेत क्रान्ति की कई सीमाएं भी सामने आई हैं। इनमें प्रमुख कमियां निम्न हैं –

- ऐसे अनेक गांव हैं जिनमें दूध उत्पादन की क्षमता है लेकिन उन्हें ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।
- पशु स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से बड़ी संख्या में पशु संक्रमण रोगों के कारण मरते हैं।
- दूध उत्पादकों को दूध की लाभकारी कीमत नहीं मिल पाती है। सहकारी कम्पनिया जिस दूध को शहरों में 25 से 26

रुपये प्रति लीटर बेचती हैं वही दूध वे किसानों से मात्र 13 से 14 रुपये लीटर की दर से खरीदती हैं।

- देशभर में किसानों व पशुपालकों द्वारा उत्पादित कुल दूध के मात्र 15 प्रतिशत का ही प्रसंस्करण संगठित क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु कुछ सकारात्मक प्रयास आवश्यक हैं–

- निरन्तर अनुसंधान।
- आधुनिक डेयरियों की स्थापना।
- दुग्ध संयंत्रों की स्थापना।
- पशु–नस्ल सुधार योजना।
- चारा बैंकों की स्थापना।
- पशु डेयरी विकास परियोजना।
- पशुधन बीमा योजना।
- पशु चिकित्सा व्यवस्था।
- दुग्ध संगठनों की स्थापना।

ऊपर दिए गए विवरण, दुग्ध क्षेत्र द्वारा की जा रही अनवरत प्रगति, दुग्ध उत्पादन हेतु सरकार द्वारा दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों और सुविधाओं, निरन्तर चलने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों, दुग्ध संगठनों के सकारात्मक प्रयासों और दुग्ध परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के आधार पर कहा जा सकता है कि हमें द्वितीय श्वेत क्रान्ति के उद्देश्य में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और भारत पौराणिक साहित्य में किए गए उल्लेखों के अनुसार स्वयं में 'क्षीर सागर' बन जाएगा। 2012 में 122 करोड़ जनसंख्या पर 529.7 मिलियन पशु उन्नत डेयरी विकास में योगदान देकर कृषि सहभागिता का पर्याय बनकर कृषकों की उन्नत स्थिति में भी योगदान देंगे।

प्रवक्ता, समाजशास्त्र
महिला पी.जी. महाविद्यालय, जोधपुर
ई–मेल : sunitammv@gmail.com

Scanned by CamScanner